

भाग एक : अर्थव्यवस्था – समीक्षा और संभावनाएं

I

मूल्यांकन और संभावनाएं

1.1 वित्तीय वर्ष 2019-20 आधा बीत चुका है और वैश्विक अर्थव्यवस्था तथा भारत के लिए अल्पकालीन परिदृश्य पर कई अनिश्चितताओं का बोझ है। जनवरी-मार्च 2018 की प्रबल संवृद्धि के बाद परवर्ती महीनों में वैश्विक अर्थव्यवस्था धीमी पड़ने लगी। गति का यह नुकसान विभिन्न हिस्सों में पसरा क्योंकि समूचे विश्व में राजनैतिक घटनाक्रमों से अनिश्चितताएं बढ़ीं, विश्व व्यापार ठंडा पड़ा, तथा निवेश पस्त और विनिर्माण कमजोर हो गया। वर्ष 2018 के आरंभिक महीनों से ही वैश्विक घटनाओं-प्रणालीगत केंद्रीय बैंकों द्वारा मौद्रिक नीति के सामान्यीकरण के प्रयास; कच्चे तेल की बढ़ती और अस्थिर कीमतें; भू-राजनैतिक तनाव; व्यापारिक तनाव; और ब्रेकिज़ट – के प्रभावों के सम्मिश्रण ने सुरक्षित ठिकानों (सेफ़ हेवन्स) की ओर पलायन प्रारंभ करा दिया और एक आस्ति वर्ग के रूप में पूंजीगत प्रवाहों को उदीयमान बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) से बाहर कर दिया। झंझावात के झटकों ने वित्तीय बाजारों को डांवाडोल कर दिया, जिसके परिणाम मुद्रा में मूल्यहास, आस्ति कीमतों में उतार-चढ़ाव, मुद्रा भंडार में गिरावट और समष्टि आर्थिक नुकसान के रूप में आए जिनसे ईएमई अक्टूबर 2018 के आरंभ तक लगभग निरंतर प्रभावित रहीं। वैश्विक घटनाओं के भँवर के कुछ धीमे पड़ने के बाद ही आगामी महीनों में शांति वापस आई। इन नकारात्मक बाह्य घटनाओं से भारत भी अछूता नहीं रहा।

1.2 भारत की वास्तविक जीडीपी ने 2014-18 के दौरान औसतन 7.7 प्रतिशत की और 2018-19 की पहली तिमाही में 8 प्रतिशत की संवृद्धि दर्ज की, लेकिन वर्ष 2018-19 के शेष समय में इसने अपना वेग गंवाना शुरू कर दिया। वर्ष 2018-19

की शुरूआत प्रखर हुई लेकिन बाद में अप्रत्याशित अस्थिरता और बदलाव के मोड़ आए जिनका भारत के समष्टि आर्थिक प्रदर्शन पर बुरा असर पड़ा। विभिन्न समयों पर संवृद्धि के संचालकों को गिरावट के झटके लगे। दूसरी तिमाही में सकल स्थाई पूंजी का निर्माण धीमा पड़ा, जो कि परवर्ती तिमाहियों में और भी गहराता गया और इसका दुष्प्रभाव दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही में विनिर्माण और निवल निर्यातों पर रहा। शेष विश्व की ही तरह निजी उपभोग समुत्थानशील बना रहा, जिससे सेवाओं को सहारा मिलता रहा। तथापि, वर्ष की दूसरी छमाही से लेकर और इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक, भारत में समग्र मांग का यह मुख्य आधार उससे कहीं अधिक कमजोर हुआ है जितनी प्रत्याशा आरंभ में थी। इस बीच तीसरी तिमाही से कृषि और सहायक क्रियाकलापों में मूल्य-वर्धन की वृद्धि में हास हुआ जिसने फलस्वरूप ग्रामीण मांग को नीचे खींच दिया है।

1.3 भारत की समष्टि आर्थिक स्थिरता ने आशा की एक किरण दिखाई जिसमें मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के तहत लगातार दूसरे वित्तीय वर्ष भी मुद्रास्फीति 4 प्रतिशत के निर्धारित लक्ष्य से नीचे ही बनी रही; चालू खाता घाटा (सीएडी) चौथी तिमाही (2018-19) में जीडीपी के 1 प्रतिशत से नीचे रहा; और समग्र वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3.4 प्रतिशत पर रोका जा सका। आने वाले निवल पूंजी प्रवाहों की तुलना में सीएडी अधिक होने के कारण बाह्य क्षेत्र के समक्ष 2018-19 में मुश्किलें खड़ी हुईं, परंतु आरक्षित मुद्रा भंडार में हुई क्षति की आंशिक भरपाई वर्ष के अंत तक हो गई। तो भी, अभी यह अस्पष्ट है कि इस स्थिरता ने गतिविधियों की गहरी हानि को कम किया या फिर अपने आप में यह धीमेपन

\* भारतीय रिज़र्व बैंक का लेखा वर्ष जुलाई-जून है, लेकिन कई चरों से संबंधित आंकड़े वित्तीय वर्ष, अर्थात् अप्रैल-मार्च के आधार पर उपलब्ध होते हैं। अतः आंकड़ों का विश्लेषण वित्तीय वर्ष के आधार पर किया गया है। उपलब्धता के अनुसार, मार्च 2019 के बाद के आंकड़े शामिल करते हुए अद्यतन स्थिति प्रस्तुत की गयी है। विश्लेषण के प्रयोजन से तथा नीतियों का उचित परिप्रेक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए इस रिपोर्ट में आवश्यकतानुसार पिछले वर्षों के तथा भावी अवधि के संदर्भ भी दिए गए हैं।

का ही लक्षण बनकर आई। यह दुविधा तब और भी गहरी हो जाती है जब इसे वित्तीय स्थिरता से जुड़े मुद्दों के साथ देखा जाए। बैंकों के बैलेंस-शीटों में चल रहे सुधारों और पूँजी बफर्स के पुनर्निर्माण से दबावग्रस्त आस्तियों की वृद्धि में एक ठहराव आया और संवृद्धि के आवेगों को फिर से बल मिलने की उम्मीद में ऋण प्रवाहों (क्रेडिट फ्लो) में स्पंदन पैदा हुआ। सकल मांग के व्यापक रूप से सुस्त पड़ने से वित्तीय स्थिरता की बहाली में हुई प्रगति भी गैर-बैंकिंग क्षेत्र में चलनिधि और क्रेडिट के दबाव के कारण जोखिम में पड़ सकती है, हालांकि रिज़र्व बैंक इन पर ध्यान दे रहा है।

1.4 भारतीय अर्थव्यवस्था जब 2019-20 के आने वाले शेष समय की ओर देखती है, तो उसके सामने सबसे अहम सवाल है: हमारा सामना किससे है – किसी सॉफ्ट पैच (अल्पावधि सुस्ती) से या किसी चक्रीय अधोगति से या फिर संरचनागत धीमेपन से? यह तय करेगा कि कौन से नीतिगत कदम उठाए जाएंगे – उदाहरण के तौर पर, सॉफ्ट पैच को अनदेखा किया जा सकता है, जबकि चक्रीय अधोगति के लिए जरूरी होगा कि मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों के रूप में प्रतिचक्रीय कार्रवाई की जाए, लेकिन संरचनागत धीमेपन के लिए कठोर सुधार आवश्यक होंगे। रोग की पहचान कठिन है; इन स्थितियों को साफ-साफ सुलझा लेना, कम-से-कम शुरुआती दौर में तो, कठिन है ही। वर्ष 2018-19 के अनुभव से मिली सीख में शायद कुछ नजदीकी उत्तर मिल जाए, जिसकी सहायता से वर्ष 2019-20 के परिदृश्य और आगामी चुनौतियों का आकलन हो पाए।

### वर्ष 2018-19 के अनुभव का सबक

1.5 जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, समष्टि आर्थिक और वित्तीय स्थितियों में अप्रत्याशित बदलावों और महज इनके आकार-प्रकार के लिहाज से वर्ष 2018-19 की डगर बहुत कठिन रही। इसके अंतर्निहित संचालकों को जानने के लिए इन बड़े घटनाक्रमों को बारीकी से परखें तो अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति और उस संदर्भ में नीतिगत परिप्रेक्ष्यों को समझा जा सकता है।

1.6 वैश्विक राजनैतिक पटल पर पूरे वर्ष संरक्षणवादी नीतियों की घोषणा तथा नाम लगाने (लेबलिंग), द्विपक्षीय टैरिफ बढ़ाने,

प्रतिबंधों और प्रतिकार रूप में की जाने वाली कार्रवाइयां छाई रहीं। इन्होंने विश्व व्यापार को गहरा आघात पहुंचाया, वित्तीय बाजारों को बेचैन किया और व्यापार के माध्यम से वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ अपने को एकीकृत करने की कोशिश करने वाली कई उन्नत व उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं की समष्टि आर्थिक संभावनाओं के लिए समान रूप से जोखिम पैदा किया। इनसे वैश्वीकरण के समापन को लेकर जोरदार चर्चाओं की शुरुआत भी हुई। तो भी, वर्ष के दौरान जो घटनाएं सामने आईं उनसे प्रकट होता है विश्व जुड़ा हुआ है या कम से कम विश्वव्यापी झटकों के प्रति समान रूप से सुभेद्य बना हुआ है।

1.7 कैलेन्डर वर्ष 2018 की प्रथम तिमाही में समष्टि आर्थिक परिणाम यह संकेत देते प्रतीत हुए कि वैश्विक अर्थव्यवस्था एक वर्धित प्रसारकारी चरण में थी। प्रबल मांग की प्रत्याशाओं की पुष्टि में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गईं। अत्यधिक उदारवादी मौद्रिक नीति के सामान्यीकरण की वकालत हुई और ब्याज दर वृद्धि फेड द्वारा बैलेंस-शीट को कुछ संकुचित किए जाने के कारण और ईसीबी द्वारा मात्रात्मक सुलभता की क्रमशः कमी (टेपरिंग डाउन) के रूप में इसे कुछ समर्थन भी मिला। इसके परिणामस्वरूप उदीयमान बाजारों से पूँजी के बाहर जाने की मची भगदड़ ने क्षेत्रों को लेकर कोई भेद नहीं किया, चाहे वे उच्च संवृद्धि वाली अर्थव्यवस्थाएं हों या मंदी की स्थितियों से लड़खड़ाते हुए बाहर आने वाली। प्रतीत हो रहा था कि मूलभूत पक्ष (फंडामेंटल्स) पूँजी प्रवाहों के मुख्य निर्धारक नहीं हैं। आगे साल के अंत की तरफ, जब संवृद्धि-संभावनाएं मरीचिका सिद्ध हुईं और आगामी महीनों में मंदी व्यापक हो गई, तो सभी ईएमई प्रभावित हुईं, भले ही उनमें विकास का स्तर या समष्टि आर्थिक स्थितियों की पृष्ठभूमि चाहे जो रही हो।

1.8 इन घटनाक्रमों से ज्ञात होता है कि अर्थव्यवस्थाओं को कैसे प्रभावों के विरुद्ध अपने लिए मजबूत बफर बनाने होंगे जो सीमा पार जाते हैं, विशेषतः यह देखते हुए कि न तो वैश्विक सामूहिक कार्रवाई तय है और न ही वैश्विक वित्तीय सुरक्षा कवच। इस संदर्भ में विश्वव्यापी घटनाओं के हानिकारक प्रभावों से निपटने के लिए जरूरी है कि सभी ओर से अधिकाधिक संवदेनशीलता बरती जाए और खेल के मौजूदा नियमों का

पालन भी हो। उदीयमान बाजारों से होने वाले स्पिल-बैक अब वैश्विक आर्थिक संभावनाओं के लिए एक वास्तविक खतरा बन चुके हैं। बहुपक्षीय समाधान वांछनीय हैं बजाय अदूरदर्शी कार्रवाइयों के जिनसे वैश्विक कल्याण में कमी आती है। वैश्विक अंतर-सम्बद्धता की अधिकता को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा इस साल (अप्रैल 2019) की अपनी वैश्विक नीति की कार्यसूची में लिए गए इन्टीग्रेटेड पॉलिसी फ्रेमवर्क (आईपीएफ) से आगे का रास्ता मिल सकता है, जिसमें मौद्रिक, विनियम दर, समष्टि विवेकपूर्ण और पूंजी प्रवाह प्रबंधन नीतियों और उनकी अंतर्क्रियाओं पर संयुक्त रूप से विचार की बात है। सहकारिता की भावना और सभी भागीदारों द्वारा इसे स्वीकृति देने पर ही इसकी प्रभावशीलता टिकी हुई है।

1.9 इस विश्वव्यापी मंदी के संक्रमण के कई चैनल हैं। भारत के लिए, मामूली वास्तविक मूल्य-हास के बावजूद निर्यात की मात्रा पहले से कम रही, जो यह दिखाता है कि निर्यात में विदेशी मांग से ही किसी अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन तय होता है। इसके अलावा वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं और 'बाजार के अनुसार कीमत' रणनीति के प्रसार के कारण विनियम दर से होने वाले लाभ (एक्सचेंज रेट पास थ्रू) कम ही रहे। व्यापार की शर्तें एक अन्य चैनल के रूप में आई : ओपेक और उत्पादन कटौती, बढ़ी हुई शेल आपूर्ति और सोशल मीडिया वक्तव्यों के घमासान के बीच इस साल के अधिकांश भाग में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ीं और अस्थिर रहीं। इस बीच धीमी पड़ रही घरेलू मांग से तेल-इतर बुलियन-इतर आयातों में नरमी आई। एकपक्षीय व्यापारिक कार्रवाइयों की बढ़ती हुई घटनाओं के कारण अवसरानुकूल निर्यात रणनीति की जरूरत है जो (i) बड़े खिलाड़ियों द्वारा महत्वपूर्ण स्थलों को रिक्त करे और व्यापार के दिशा परिवर्तन से पैदा हुए खाली स्थान को हासिल करे; (ii) उत्पादों और बाजारों की विविधता में तेजी लाए; और (iii) आंतरिक सुदृढ़ता और प्रतिस्पर्धी लाभ पर आगे बढ़े। साथ ही साथ ऐसे प्रयासों को द्विगुणित करना होगा जो विद्यमान संस्थागत व्यवस्था के तहत ही देशों को सहकारी बहुपक्षीय व्यवस्थाओं की तरफ ले जाएं, राष्ट्रों के आत्महित का त्याग करें और ऐसी बहुपक्षीय व्यापारिक व्यवस्था का सूत्रपात करें जिसमें सभी सम्मिलित हों।

1.10 वर्ष 2018-19 के दौरान के व्यापारिक युद्धों एवं वैश्विक घटनाओं के अन्य स्रोतों ने भारत को एक अन्य मार्ग से भी प्रभावित किया और वह है वित्त और कॉन्फिडेंस के चैनलों का आपसी संगुणन। पोर्टफोलियो पूंजी की वैश्विक घटनाओं के प्रभावों के प्रति संवेदनशीलता के बारे में अनुमान है कि यह टेपर-टेन्टम अवधि की तुलना में कई गुना बढ़ गई है। इसका श्रेय 'निष्क्रिय निवेश' रणनीतियों के हावी होने को जाता है, जिसमें निधि प्रबंधक (फंड मैनेजर्स) किसी सूचकांक विशेष या बेन्चमार्क पर प्रतिलाभों को ट्रैक करते हुए एक्सचेंज ट्रेडेड फन्ड जैसे उपादानों का प्रयोग करते हैं। परिणामस्वरूप, मनोभावों में जोखिम-शुरू जोखिम-खतम के आवर्तनों ने पूंजी प्रवाहों की गतिशीलता और परिवर्तनीयता को बढ़ा दिया, जिसके दुष्प्रभाव वित्तीय बाजारों और आखिरकार आर्थिक क्रियाकलापों तक पहुंच गए। भारत जैसे देश के लिए, जहाँ पारंपरिक रूप से चालू खाता घाटा बना रहता है, व्यवहार्य बाह्य वित्तपोषण, पर्याप्त एहतियाती बफर रखने का एक अतिरिक्त तर्क बन सकता है। वर्ष 2018-19 का अनुभव याद रखना समझदारी होगी जब साल की पहली तीन तिमाहियों में कच्चे तेल की कीमतों के कारण चालू खाता घाटे में हुई वृद्धि के साथ-साथ जोखिम-विमुख पोर्टफोलियो के बाहर चले जाने की वजह से फाइनेंसिंग की जरूरतों को आरक्षित मुद्रा भंडारों (रिजर्व्स) से पूरा करना पड़ा।

1.11 घरेलू विनिर्माण और निवेश में वैश्विक संवेगों के लिए व्यापार चैनल स्वयं ही एक माध्यम बन गया है, जो कि विभिन्न देशों में औद्योगिक उत्पादन में शिथिलता और 'निवेश विमुखता' के लगभग एक साथ घटित होने में दिख रहा है। भारत में औद्योगिक आउटपुट और इसके प्रमुख घटक-विनिर्माण- में 2012-19 के दौरान 4 प्रतिशत से नीचे की गिरावट के ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में रोजगार और आय-सृजन के संदर्भ में वृहत्तर परिणाम हैं। यद्यपि, पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में सतत कमजोरी से निवेश में गिरावट को लेकर फिक्र सामने आई है तथापि, उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं का धीमा निष्पादन भी चिन्ता का कारण है। इसी के साथ प्रमुख उपभोक्ता वस्तुओं की कम्पनियों की बिक्री में भी

गिरावट आई है और एफएमसीजी उत्पादों की मात्रात्मक वृद्धि की दर घटकर इकाई अंकों में आ गई। स्पष्ट है कि विगत वर्षों की तुलना में वर्ष 2018-19 में कमजोर फसल और फसलों की कम कीमतों के कारण ग्रामीण मांग में गिरावट आई है। इससे यह चिंता सामने आई है कि इस समग्र मंदी में उपभोग ने निवेश का साथ ले लिया है, जो कि चिन्ताजनक है क्योंकि जीडीपी का 57 प्रतिशत हिस्सा उपभोग से ही आता है। स्वाभाविक है कि यह चुनौती नीतिगत प्राथमिकताओं में ऊपर आएगी।

1.12 यद्यपि भारत में उपभोग ही घरेलू मांग की आधारशिला है तथापि संवृद्धि की राह में निवेश ही निर्णायक मोड़ लाता है – अर्थव्यवस्था में सुस्थिर उच्च संवृद्धि के चरणों की शुरुआत सामान्यतया निवेश में उछाल से होती है और इसका *व्यतिक्रम* भी उतना ही सही है। निवेश दर – जीडीपी में सकल पूंजी निर्माण के अनुपात से आकलित – वर्ष में गिरकर 32.3 प्रतिशत पर आ गई। वर्ष 2017-18 की दूसरी छमाही से इसमें बहुत मामूली सुधार आ रहा था पर महज 12 माह की अवधि में यह अपनी गति खो रही है। सर्वे-आधारित मापदंडों से ज्ञात होता है कि क्षमता उपभोग का स्तर ट्रेंड से अधिक रहा, जो सामान्यतः नए क्षमता वर्धन में निवेश की वजह होता है। लेकिन, वर्तमान में पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) का चक्र शांत है – मांग पूरी करने के लिए फर्मों द्वारा क्षमता को बढ़ाने के स्थान पर विद्यमान क्षमता का ही भरपूर दोहन करने को प्राथमिकता दी जा रही है। विनिर्माता कंपनियों की बिक्री में ढलान से मनोभाव (सेंटिमेंट्स) प्रभावित हो रहे हैं। आदिम उत्साह (एनिमल स्पिरिट्स) को हुआ क्या है? इसके केन्द्र में मुद्दा है घरेलू मांग का। और नीति का फोकस क्या होना चाहिए? कारोबार करने में सहजता, उत्पादन के घटकों *यथा* भूमि और श्रम में सुधार; व्यापार के बढ़ते हुए तनावों (जैसा कि पैरा-1.9 में उल्लेख किया गया है) के कारण मिलने वाले अवसरों का लाभ उठाने; और लोक प्राधिकारियों द्वारा पूंजीगत खर्चों का अधिक तेजी से कार्यान्वयन और ऐसे ही अन्य उपायों पर लगातार फोकस किया जाए तो अर्थव्यवस्था में संवृद्धि के आवेग लाए जा सकते हैं।

1.13 वर्ष 2016-17 और 2017-18 में लगातार रिकार्ड पैदावार के कारण कृषि क्षेत्र में, मांग की तुलना में अतिरिक्त

आपूर्ति से नीति निर्धारकों को अतिरिक्त खाद्य प्रबंधन – विशाल बफर स्टॉक; पूरे विश्व में कृषि उत्पादों की अतिरिक्त आपूर्ति के चलते अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए कम व्यवहार्य अवसर; भारत में संरचनागत रूप से खाद्य की कम कीमतें; और कम कृषि आय, और ये सब एक स्वपोषित चक्र में – के पूर्वानुभव संशय (डेजा वू) का सामना करना पड़ा है। मूलभूत तथ्य यह है कि कुल श्रमसंख्या का 44 प्रतिशत कृषि क्षेत्र में लगा हुआ है जो लगभग 3.1 प्रतिशत (2011-12 से 2017-18) की औसत वार्षिक संवृद्धि के साथ सकल वर्धित मूल्य का लगभग 17 प्रतिशत ही उत्पन्न कर पाता है।

1.14 मूल्य स्थिरता के लिए निम्न खाद्य मुद्रास्फीति के लाभ को बनाए रखते हुए कृषकों की आय स्तर को बढ़ाना वर्ष 2018-19 में एक विकट चुनौती के रूप में सामने आया। एमएसपी, ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, आपूर्ति से जुड़ी मूलभूत संरचनाओं जैसे कि सिंचाई, निविष्टियों की उपलब्धता और 'ई-नाम' के जरिए एपीएमसी को जोड़ने जैसी सामान्य सहायताओं के साथ ही केंद्र सरकार के स्तर पर प्रधानमंत्री किसान योजना और उप-राष्ट्रीय स्तर पर विविध योजनाओं के तहत प्रभावी आय अंतरण एक पसंदीदा नीतिगत पहल के रूप में उभरा। अब समय आ गया है कि कृषि क्षेत्र के प्रति समग्र नजरिए और नीतिगत हस्तक्षेपों पर पुनः विचार किया जाए। राज्यों द्वारा एपीएमसी नियमों में बदलाव अभी भी अधूरा पड़ा है, जो कृषि उत्पादों के मार्केटिंग सुधारों में बाधक साबित हो रहा है अन्यथा इससे थोक खरीदारों, खुदरा विक्रेताओं एवं निर्यातकों को सीधे ही किसानों से कृषि उत्पादों की खरीद करना आसान हो जाता। इससे किसानों को निश्चित कीमत हासिल करने और बाजार पाने में मदद मिलेगी। यदि इसे पूरा कर लिया जाए तो कृषि विपणन के क्षेत्र में यह एक निर्णायक सुधार होगा जो संपूर्ण मूल्य शृंखला में नए निवेशों को आकर्षित करेगा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास से मांग में तेजी आएगी और अपव्यय से जुड़ा घाटा कम होगा। यद्यपि समय के साथ कोल्ड स्टोरेज की संख्या बढ़ी है लेकिन भारत में बैक-एंड में अभी भी ऐसे समूहन बिंदुओं की कमी है जहां पर कृषि उत्पादों को भंडारित, ग्रेडवार पैकिंग, पूर्व-शीतलित किया जा सके एवं उनके अंतिम गंतव्यों तक भेजा जा सके। शीत आपूर्ति शृंखला

नेटवर्क में निवेश ही वह कुंजी है जिस पर भविष्य में ताजा उत्पादों की धारा प्रवाह सुपुर्दगी का दारोमदार है। ग्रामीण सड़कों एवं परिवहन की आधारभूत संरचना में निवेश के द्वारा आपूर्ति शृंखला को मजबूत बनाया जा सकता है ताकि संघटित एवं स्थानीय टकराव रहित बाजारों में किसानों को ऊँची कीमतें दिलवाने के लक्ष्य को हासिल किया जा सके।<sup>1</sup>

1.15 वित्तीय क्षेत्र की ओर रुख किया जाए तो हम पाते हैं कि पहचान, सुधार एवं समाधान के सतत प्रयासों के फलस्वरूप बैंकिंग प्रणाली का सकल अनर्जक आस्ति अनुपात (जीएनपीए) पिछले वर्ष के 11.2 प्रतिशत से घटकर मार्च 2019 में 9.1 प्रतिशत पर पहुंच गया। नई गिरावटों में कमी आई और प्रणाली-स्तरीय प्रावधान कवरेज अनुपात जो हाल तक 50 प्रतिशत के आस-पास बना हुआ था, उछलकर 60.9 प्रतिशत पर पहुँच गया। वर्ष 2019-20 के बजट आबंटन सहित ₹2.7 ट्रिलियन रुपए के पुर्नपूँजीकरण से पूँजीगत बफ़र में मजबूती आई। दबावों के घटने से बैंक क्रेडिट प्रवाह फिर जाग उठा है और उसमें व्यापकता आ रही है।

1.16 शुरुआती तीव्र रुकावटों के बाद, इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड पांसा पलटनेवाला साबित हो रहा है, वसूली में क्रमिक सुधार आने के फलस्वरूप निवेश चक्र की संभावित राह में आनेवाली बाधाएं दूर हो रही हैं। दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए रिजर्व बैंक द्वारा जून 2019 में बनाए गए मानकों में समाधान प्रक्रिया पर उधार देनेवालों को विवेकाधिकार मिलने से त्वरित समाधान को बढ़ावा मिला है। उद्देश्य यह है कि अनर्जक आस्तियों के भावी

दबाव की घेराबंदी कर बैंकिंग क्षेत्र को उससे सुरक्षित किया जा सके। बड़े एक्सपोज़र फ्रेमवर्क को संशोधित किया गया ताकि संकेंद्रण जोखिमों एवं एक्सपोज़रों का अधिक सटीकता से पता लगाया जा सके और इस फ्रेमवर्क को अंतरराष्ट्रीय उत्कृष्ट पद्धतियों के अनुरूप बनाया जा सके। घरेलू स्तर पर प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों एवं अन्य बैंकों के लिए न्यूनतम लीवरेज अनुपात में संशोधन किया गया है ताकि बासेल III मानकों के साथ बेहतर सामंजस्य स्थापित किया जा सके।

1.17 खराब आस्तियों के बढ़ते अंबार ने जहां बैंकिंग प्रणाली द्वारा दी जानेवाली उधारी में बाधा उत्पन्न की वहीं अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को संसाधन उपलब्ध कराने के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) मध्यस्थ के रूप में सामने आईं। जैसा कि वर्ष 2018-19 की घटनाओं ने दर्शाया, आस्ति देयता असंतुलन के साथ ही विवेकहीन अति और अत्यधिक ओवरलीवरेजिंग थी। यद्यपि, बैंकिंग एवं गैर-बैंकिंग क्षेत्र की कुल आस्तियों में एनबीएफसी का हिस्सा लगभग 12 प्रतिशत है तथापि, छिटपुट एवं बड़ी ऋण घटनाओं से उपजे दबाव तथा चलनिधि की कमी की व्यापक धारणा ने उजागर किया कि किस हद तक वित्तीय प्रणाली एवं प्रणालीगत प्रभाव आपस में जुड़े हुए हैं। एनबीएफसी के विनियामक फ्रेमवर्क एवं चलनिधि को मजबूत करने के चल रहे प्रयासों में इस अनुभव का उपयोग होगा, विशेषतः विनियामक अंतरपणन (रेग्युलेटरी आर्बिट्राज) को हटाए जाने के प्रयासों में।

<sup>1</sup> कृषि उत्पाद बाजार विनियमन अधिनियम ने राज्य सरकारों को यह अधिकार प्रदान किया कि वे थोक बाजारों की विपणन पद्धतियां स्थापित करें एवं उनका विनियमन करें। समय के साथ, बिचौलियों की बढ़ती संख्या ने किसानों एवं उपभोक्ताओं के बीच एक दीवार सी खड़ी कर दी। राज्य द्वारा विनियमित बाजारों में कमीशन एजेंटों के लाइसेंसिंग से लाइसेंसी व्यापारियों के एकाधिकार को बढ़ावा मिला और नए उद्यमियों के बाजार में दाखिल होने में प्रमुख बाधा साबित हुआ। फलस्वरूप, कृषि विपणन सुधारों (2002) पर गठित अन्तर-मंत्रालयी कार्यदल ने यह सिफारिश की कि कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी) अधिनियम में संशोधन किया जाए ताकि प्रत्यक्ष विपणन एवं निजी तथा सहकारी क्षेत्र द्वारा कृषि बाजारों की स्थापना के लिए अनुमति दी जा सके जिससे विपणन अधिक कुशलता से हो एवं निजी निवेश के अनुकूल माहौल बनाया जा सके। इस पर कार्य करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने राज्य सरकारों के परामर्श से कृषि विपणन पर राज्यों के लिए एक मॉडल अधिनियम प्रस्तावित किया। कुल मिलाकर 19 राज्यों ने अपने एपीएमसी नियमों में संशोधन किया है ताकि थोक विक्रेता, खुदरा व्यापारी एवं निर्यातक सीधे ही किसानों से कृषि उत्पादों की खरीद कर सकें। उड़ीसा, नागालैंड, सिक्किम, महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तराखंड जैसे राज्यों ने निजी बाजार यार्ड/निजी बाजार स्थापित किए हैं। इनमें से अधिकांश राज्यों ने कृषि उत्पादों के ई-कारोबार को बढ़ावा देने के लिए पण्य बाजार नियामक – वायदा बाजार कमीशन के तहत पंजीकृत पण्य एक्सचेंजों को प्रत्यक्ष विपणन लाइसेंस भी प्रदान किए हैं। संशोधित एपीएमसी अधिनियम को सही तरीके से लागू करने पर कृषक उत्पादक संगठनों एवं स्व सहायता समूहों से कारोबारी जगत सीधे संपर्क कर कृषि उत्पाद खरीद सकेगा। इससे किसानों को नियत कीमतों एवं बाजार में पहुँच का फायदा मिलेगा तथा कारपोरेट इकाइयों को बैकवर्ड लिंकेज स्थापित करने एवं गुणवत्ता नियंत्रण के आश्वासन का लाभ भी मिल सकेगा।



1.18 कम नकदीवाली अर्थव्यवस्था की दिशा में भुगतानों के इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के प्रयोग को बढ़ाने में वर्ष के दौरान उल्लेखनीय प्रगति हासिल की गई। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, खुदरा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान लेन-देनों में 59 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और पिछले वर्ष के 14.6 बिलियन से बढ़कर 23.3 बिलियन हो गए, जिसके परिणामस्वरूप कुल खुदरा भुगतान में इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन की मात्रा पिछले वर्ष के 92.6 प्रतिशत से बढ़कर 95.4 प्रतिशत हो गई। फिनटेक एवं डिजिटलीकरण संवृद्धि के नवीन वाहक के रूप में सामने आए। हालांकि नीतिगत चुनौती डाटा एवं टेक्नालाजी के दुरुपयोग से जुड़े जोखिमों को कम करने के साथ डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार का संतुलन बिठाने की है ताकि आम जनता का विश्वास और भरोसा कायम रहे तथा भुगतान एवं निपटान प्रणाली की दक्षता एवं सुदृढ़ता सुनिश्चित की जा सके। 'रिपोर्ट ऑन बेंचमार्किंग इंडियास पेमेंट सिस्टम्स ( जून 2019)' में भारतीय भुगतान प्रणालियों का व्यापक मूल्यांकन बताता है कि डिजिटल लेन-देन से जुड़े कई मानकों, टेक्नोलॉजी, मूलभूत संरचना तथा भुगतान और निपटान नियम एवं विनियम के मामले में अपने समकक्ष देशों की तुलना में भारत आगे/मजबूत स्थिति में है। बावजूद इसके, जैसा कि गत वर्ष का अनुभव रहा, यही वे क्षेत्र हैं जिनमें विनियामकों को सतत नवोन्मेषी प्रयास करने हैं और खुदरा भुगतान व निपटान प्रक्रियाओं में हो रही प्रगति तथा भुगतान लिखतों के चयन के संबंध में समय के साथ चलना है। हालांकि इसमें उल्लेखनीय प्रगति हासिल हुई है, फिर भी विशाल संभावनाएं मौजूद हैं।

1.19 इन घटनाक्रमों की पृष्ठभूमि में, इस अध्याय में पहले उठाए गए प्रश्न पर वापस आना उपयुक्त होगा। सकल और क्षेत्रगत आर्थिक गतिविधि के विभिन्न मौसमी समायोजित संकेतकों को प्रवृत्ति एवं चक्रीय घटकों में अलग-अलग करके देखें तो यह संकेत मिलता है कि हालिया नरमी ऐसी अल्पावधि सुस्ती (सॉफ्ट पैच) हो सकती है जो चक्रीय अधोगति में बदले न कि गहरी संरचनागत मंदी में। हालांकि, अभी भी भूमि, श्रम, कृषि विपणन आदि में

संरचनागत मुद्दे हैं जिनका समाधान किया जाना जरूरी है। अलग-अलग विश्लेषण इस बात की पुष्टि करते हैं कि विनिर्माण, व्यापार, होटल, परिवहन, संचार एवं प्रसारण, निर्माण एवं कृषि जैसे कई क्षेत्रों में व्यापक चक्रीय गिरावट चल रही है। तथापि, यह देखा जाना महत्वपूर्ण है कि वर्ष 2016-17 से रुझान संवृद्धि (ट्रेंड ग्रोथ) में थोड़ी नरमी आई है जिसके लिए सेवा क्षेत्र, विशेषकर व्यापार, होटल, परिवहन, संचार एवं प्रसारण तथा वित्तीय, रियल इस्टेट एवं पेशेवर सेवाएं जिम्मेदार हैं। इन क्षेत्रों की समस्याओं एवं चुनौतियों का समाधान किए जाने की जरूरत है ताकि व्यापक बेहतरी हासिल की जा सके।

1.20 इन सरलीकृत तथ्यों एवं अनुभवजन्य निष्कर्षों ने वर्ष 2018-19 के दौरान मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियों की दिशा तय की। इनका ध्यानपूर्वक मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है, इसलिए कि यदि गिरावट लंबी खिंचे तो कम से कम यह जाना जा सके कि प्रति-चक्रीय नीतिगत कार्रवाइयों की कितनी गुंजाइश है।

1.21 राजकोषीय नीति से शुरुआत करें तो, बावजूद इसके कि जीएसटी व अन्य अप्रत्यक्ष करों और आय कर में भी होनेवाले संग्रहण में कमी से समग्र कर-संग्रहण उछाल में गिरावट आई, केंद्र सरकार का सकल राजकोषीय घाटा मोटे तौर पर वर्ष 2018-19 के बजट लक्ष्य के अनुरूप रहा। खर्च की दृष्टि से देखा जाए तो पूंजीगत व्यय की तुलना में राजस्व व्यय के अनुपात के रूप में आकलित खर्चों की गुणवत्ता में जो सुधार वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में हुआ था उसे वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में कायम नहीं रखा जा सका। इसके अलावा, 2007-08 से ही प्राथमिक अधिशेष (सकल राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को घटाने के बाद) हासिल नहीं किया जा सका है।

1.22 राज्यों के मामले में, 2018-19 के लिए वास्तविक राजकोषीय स्थिति पर कृषि-ऋण माफी, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन और आय समर्थक योजनाओं के

वित्तपोषण का प्रभाव पड़ना जारी रह सकता है। फलस्वरूप, आवश्यकतापड़नेपर अर्थव्यवस्था को दिए जाने वाले राजकोषीय प्रोत्साहन की गुंजाइश बहुत कम है। फिर भी केंद्र एवं कुछ राज्यों द्वारा मकान किराया भत्ता एवं 7वें वेतन आयोग से जुड़े क्रमिक एरियर भुगतान के बाद एक अल्प राजकोषीय प्रोत्साहन दिया गया। सरकारी अंतिम उपभोग व्यय (जीएफसीई) को छोड़ दें तो, वास्तविक जीडीपी संवृद्धि वर्ष 2017-18 में 0.8 प्रतिशतता अंक एवं 2018-19 में 0.3 प्रतिशतता अंक से कम रहती।

1.23 उभरते मुद्रास्फीति एवं संवृद्धि समीकरण में विपरीत बदलावों को संभालने के लिए मौद्रिक नीति के संचालन को द्विपक्षी होना पड़ा। वर्ष 2018-19 की पहली छमाही में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की ऊँची कीमतों, वित्तीय बाजार की उथल-पुथल एवं मजबूत अंतर्निहित मुद्रास्फीति के चलते बढ़ते मुद्रास्फीतिकारक दबावों को देखते हुए मौद्रिक नीति को सख्त किया गया। अक्टूबर 2018 में नीतिगत दर में 50 आधार अंकों की संचयी बढ़ोतरी के बाद नीतिगत रुख को तटस्थता से नपी-तुली सख्ती की ओर मोड़ा गया। तथापि, आनेवाले महीनों में व्यक्तिगत आर्थिक एवं वित्तीय स्थितियों में नाटकीय बदलाव आया। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के चलते मुद्रास्फीति में सुधार हुआ और खाद्य पदार्थों की कीमतें अपस्फीति में डूब गईं। उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति 2018-19 में औसतन 3.4 प्रतिशत रही, यानी मौजूदा मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के अंतर्गत संदर्भाधीन अवधि में लगातार दूसरे वित्तीय वर्ष 4 प्रतिशत के लक्ष्य से कम। यद्यपि मुद्रास्फीति जोखिम कम हुए लेकिन बिगड़ते वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के चलते घरेलू गतिविधि धीमी पड़ गई। तदनुसार, फरवरी 2019 में नीतिगत दर में कटौती की गई और मौद्रिक नीति रुख को बदलकर तटस्थ किया गया। जैसा कि अगले भाग में विस्तार से बताया जाएगा, इसके बाद और भी निभावकारी एवं चलनिधि संबंधी कार्रवाइयां की गई हैं ताकि प्रणाली में चलनिधि भरपूर रहे।

1.24 पूरे 2018-19 में, रिजर्व बैंक ने सक्रिय रूप से विभिन्न परिपक्वताओं वाली रेपो/रिवर्स रेपो, पूर्णतया खुला बाजार परिचालन (ओएमओ) एवं विदेशी मुद्रा स्वैप जैसे विभिन्न प्रकार के लिखतों के माध्यम से चलनिधि की उपलब्धता सुनिश्चित की। जून-अगस्त 2018 के दौरान नीतिगत दर में 50 आधार अंकों की बढ़ोतरी की प्रतिक्रिया में बैंकों की जमा एवं उधार दरों में वृद्धि हुई। तथापि, अलग-अलग क्षेत्रों में इसका संचरण असमान रहा और सर्वाधिक असर नए रुपया ऋण पर भारित औसत उधार दर (डब्ल्यूएएलआर) पर हुआ जिसमें जून 2018-जनवरी 2019 के दौरान 57 आधार अंक की बढ़ोतरी हुई। फरवरी 2019 की मौद्रिक नीति कार्रवाई के बाद, जिसे अप्रैल एवं जून में पुनः बल दिया गया, बैंकिंग प्रणाली एवं वित्तीय बाजारों में ब्याज दरों में मामूली नरमी आई। इसके बारे में आगामी खंड में चर्चा की जाएगी।

### 2019-20 के लिए संभावनाएं

1.25 वर्ष 2019-20 आगे बढ़ रहा है और समष्टि-आर्थिक परिवेश उलझा सा है एवं वित्तीय बाजारों में अत्यधिक अस्थिरता अनुभव की जा रही है। वैश्विक आर्थिक गतिविधियां जनवरी-मार्च 2019 के दौरान बहाल हो जाएंगी, खासतौर से उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में, जहाँ कि मंदी के हालात को देखते हुए मौद्रिक नीति का रुख सुलभ किया गया था। कच्चे तेल की कीमतें नरम बनी रहीं और वित्तीय बाजार ने अपना खोया हुआ आधार कुछ हद तक वापस पा लिया। लेकिन आने वाले महीनों में जो आंकड़े सामने आए उन्हें देखते हुए ये उम्मीदें झूठी साबित हुईं। क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) धीमा पड़ गया है, यहाँ तक कि कुछ बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में इसमें गिरावट के संकेत हैं। जोखिम की भूख कम हो गई है तथा बॉण्डों के ऋणात्मक प्रतिफल का संसार उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में फैल गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि कई प्रकार के अधोमुखी जोखिम सच साबित होने लगे हैं जैसे व्यापार संबंधी तनाव, भू-राजनैतिक विवाद बढ़ते जा रहे हैं, और ईएमई में नये सिरे से वित्तीय अस्थिरता क्योंकि पोर्टफोलियो प्रवाहों में कमजोरी के संकेत मिलने लगे हैं। इन अनिश्चितताओं के बीच वित्तीय बाजारों में बेचैनी और अस्थिरता बनी हुई है, जो विश्व के संवृद्धि संबंधी पूर्वानुमानों के बार-बार डाउनग्रेड होने में दिखाई दे रही है। उल्लेखनीय है कि आईएमएफ का अनुमान

है कि विश्व की समृद्धि दर पिछले वर्ष के 3.6 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2019 में 3.2 प्रतिशत हो जाएगी जो कि अक्टूबर 2018 से लेकर अब तक कमी करने वाला लगातार चौथा संशोधित पूर्वानुमान है। केंद्रीय बैंक नीतिगत दरों में कटौती करते हुए अधिकांशतः निभावकारी नीति अपनाने की ओर बढ़ रहे हैं। इस स्थिति ने इन आशंकाओं को और भी हवा दी है कि विश्व की अर्थव्यवस्था उससे कहीं ज्यादा कमजोर हो सकती है जितना हेडलाइन के आंकड़े संकेत दे रहे हैं।

1.26 भारत के संबंध में, एमपीसी ने अगस्त 2019 की अपनी बैठक में यह अनुमान लगाया है कि वर्ष 2019-20 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.9 प्रतिशत रहेगी, जिसमें जोखिम का झुकाव कुछ नीचे की ओर होगा। 2019-20 के वास्तविक जीडीपी वृद्धि का पहला अनुमान फरवरी 2019 में सार्वजनिक करने के बाद से एमपीसी ने अपने अनुमान को 50 आधार अंक तक कम कर दिया है। इस आधारगत अनुमान (बेसलाइन फोरकास्ट) की हाल में प्राप्त होने वाले डाटा से तुलनात्मक समीक्षा उपयोगी होगी।

1.27 उत्पादन क्षेत्र से शुरुआत करें तो हम पाते हैं कि दक्षिण-पश्चिम मॉनसून जिसका प्रभाव कृषि क्षेत्र के कार्य-निष्पादन (समग्र आर्थिक गतिविधियों का 14.4 प्रतिशत) पर पड़ता है, जमीन पर एक सप्ताह विलंब से 8 जून को आया और वायु नामक तूफान के कारण रुक गया। दक्षिण-पश्चिम मानसून की गति मध्य जुलाई से तेज हुई और 19 अगस्त, 2019 की स्थिति के अनुसार पूरे देश में वर्षा दीर्घकालिक औसत (एलपीए) से 2 प्रतिशत ऊपर रही। स्थान की दृष्टि से, मध्य भारत व दक्षिणी प्रायद्वीप में बारिश एलपीए से अधिक रही जबकि अन्य दो मौसम क्षेत्रों - उत्तर पश्चिम भारत (2 प्रतिशत) तथा पूर्व व उत्तर पूर्व भारत (14 प्रतिशत) - में एलपीए से कम रही। अंतिम कुछ हफ्तों में भरपाई के बावजूद खरीफ की बुवाई पिछले वर्ष की तुलना में 16 अगस्त 2019 की स्थिति के अनुसार 4.2 प्रतिशत कम थी। अनाजों का बफर स्टॉक 1 अगस्त 2019 की स्थिति के अनुसार मानक से 1.9 गुना अधिक था, किंतु अन्य फसलों के मामले में आपूर्ति-माँग के बीच असंतुलन को देखते हुए यदि खाद्यान्न की कीमतों को नियंत्रित रखना है तो आयात करने की ज़रूरत पड़ सकती है। 4 जुलाई को वर्ष 2019 की खरीफ़ फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 1.1-9.2 प्रतिशत तक वृद्धि की घोषणा की गई।

1.28 कृषकों की आय को दुगुना करने के उद्देश्य से संघीय बजट में नये कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) बनाने, ई-नाम के फ़ायदों को बड़ी संख्या में कृषकों को पहुँचाने तथा शून्य बजट की खेती की शुरुआत करने की रणनीति की बात कही गई है। जहाँ तक संबद्ध गतिविधियों के क्षेत्र का संबंध है, बजट में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) का प्रस्ताव किया गया है ताकि अच्छी मत्स्य-पालन प्रबंधन संरचना स्थापित की जा सके। आय में सहारा देने वाले उपायों के अलावा बजट में ग्रामीण बुनियादी सुविधा, सिंचाई तथा विपणन सहित खेती के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया गया है।

1.29 विनिर्माण और खनन क्षेत्र के कमजोर प्रदर्शन के कारण औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक अप्रैल-जून में गिर गया। दूसरी ओर, बढ़ती हुई माँग के कारण बिजली उत्पादन में मज़बूत वृद्धि ने धीमेपन को कुछ कम किया और यही स्थिति जून में भी कायम रही। उपयोग की दृष्टि से देखें तो पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन मंद रहा, जो निवेश चक्र में बेहतरी के आने के इंतज़ार में है। सीमेंट उत्पादों के कारण बुनियादी सुविधा की वस्तुओं के उत्पादन में धीमापन आना निर्माण गतिविधियों में अल्पावधि सुस्ती (सॉफ्ट पैच) का संकेत हो सकता है: जो निर्माण क्षेत्र के एक अन्य संकेतक इस्पात ने 2019-20 की पहली तिमाही में अपनी गति बनाए रखी है। हाल की एक सकारात्मक घटना अप्रैल-जून 2019 के दौरान उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं के उपयोग में 7.3 प्रतिशत की वृद्धि रही है, अलबत्ता यह काफी हद तक सूर्यमुखी तेल के उत्पादन एवं मलेरिया-रोधी औषधियों पर निर्भर है। दूसरी ओर, आँटो क्षेत्र (दुपहिया सहित) और भारी उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं (व्हाइट गुड्स) के उत्पादन में सुस्ती के साथ उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं का उत्पादन कमजोर रहा और वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में घट गया। जून 2019 में आठ प्रमुख उद्योगों का उत्पादन धीमा पड़ गया था जिसका बड़ा कारण पेट्रोलियम उत्पाद था, जो प्रमुख रिफ़ाइनरियों के अनुरक्षण हेतु अस्थायी रूप से बंद कर दिए जाने से प्रभावित हुआ था। वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में शांत बने रहने के बाद विनिर्माण क्षेत्र का क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) जुलाई 2019 में बढ़ा जो उत्पादन में गति आने, नये घरेलू आदेश मिलने तथा रोजगार द्वारा संचालित था।



1.30 जहाँ तक सेवा क्षेत्र की गतिविधियों का संबंध है वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में संपाती संकेतकों के सिगनल मिले-जुले स्वरूप के थे। परिवहन उप-क्षेत्र में, वाणिज्यिक (कमर्शियल) वाहनों की बिक्री में 2019-20 की पहली तिमाही में 9.5 प्रतिशत की गिरावट हुई एवं जुलाई 2019 तक जारी रही, जिसका आंशिक कारण प्रतिकूल आधार प्रभाव (बेस इफेक्ट) रहा है। सवारी वाहनों की बिक्री 2019-20 की पहली तिमाही में 18.4 प्रतिशत कम हो गई, जो शहरी क्षेत्र की माँग के घटने की ओर इशारा करती है। प्रमुख बंदरगाहों पर 2019-20 की पहली तिमाही में हैंडल किए गए कार्गो में वृद्धि 1.5 प्रतिशत पर धीमी बनी रही, जो निश्चित रूप से इस बात को दर्शाती है कि विश्व के व्यापार में मंदी की वजह से निर्यात और आयात की स्थिति ढलान पर थी। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्री व मालवाहक (कार्गो) ट्रैफिक अप्रैल-जून 2019 में घट गया, जिसका मुख्य कारण एक प्रमुख घरेलू एयरलाइन की सेवाओं के बंद होने का असर रहा है। लेकिन, जून में छुट्टियों के मौसम में तेजी आई और घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की संख्या सुधरी तथा उसकी वृद्धि दर क्रमशः 4.6 प्रतिशत और 2.7 प्रतिशत रही। आतिथ्य उप-क्षेत्र (हॉस्पिटैलिटी सब सेक्टर) में, अप्रैल-जून 2019 में विदेशी पर्यटकों के आगमन में 3.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो एक वर्ष पूर्व के 1.2 प्रतिशत से अधिक थी। संचार उप-क्षेत्र में, टेलीफोन ग्राहकों का आधार लगातार बढ़ रहा है, तथा अप्रैल-मई 2019 में ब्रॉडबैंड सेवाओं में हुई अच्छी वृद्धि कायम है। वित्तीय सेवाओं ने अपनी वृद्धि की हालिया रफ्तार को कायम रखा है जहाँ कि संपाती संकेतकों- बैंक क्रेडिट और सकल जमा- ने 2 अगस्त, 2019 की स्थिति के अनुसार वर्ष-दर-वर्ष आधार पर क्रमशः 12.2 प्रतिशत तथा 10.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। अप्रैल-जून 2019 के दौरान जीवन बीमा प्रथम वर्ष प्रीमियम ने भी तेजी दिखाई और 65.1 प्रतिशत की ज़बरदस्त वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की। साथ ही, 2018-19 की पहली तिमाही की तुलना में 2019-20 की पहली तिमाही में 9.8 प्रतिशत की दर से बढ़ते हुए जीवन-बीमा से इतर सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम ने भी गति बरकरार रखी है।

1.31 सकल माँग के संकेतकों की ओर रुख करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में शहरी तथा ग्रामीण दोनों घटकों

में मंद हुआ है। दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की देर से शुरुआत तथा उसके असमान वितरण से फ़सल के उत्पादन तथा ग्रामीण उपभोग की माँग के घटने का जोखिम हो सकता है। यह बात वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में मोटर साइकिल और ट्रैक्टर्स की बिक्री में क्रमशः 8.8 प्रतिशत तथा 14.1 प्रतिशत की तीव्र गिरावट से पहले ही सिद्ध हो चुकी है। हाल के समय में उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं के उत्पादन में जो तेजी आई है, यदि उसे बनाए रखा गया तो वह एक बफर हो सकता है। जहाँ तक शहरी माँग का संबंध है, यात्री-कार की बिक्री और घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या में हाल के महीनों में गिरावट दर्ज की गई है। उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं का उत्पादन जून 2019 में घट गया था (-5.5 प्रतिशत) क्योंकि टीवी सेट, हैंड टूल्स, सवारी वाहन, बिजली के उपकरण तथा दुपहिया वाहनों के उत्पादन में कमी हो गई थी।

1.32 वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में सरकारी अंतिम उपभोग व्यय (जीएफसीई), जैसा कि संघ सरकार के राजस्व व्यय में दिखा है, ब्याज भुगतान तथा सब्सिडी को घटाने के बाद पिछले वर्ष के 14.5 प्रतिशत की तुलना में काफी कम 1.7 प्रतिशत पर था। राज्य सरकारों के मामले में यह धीमापन काफी तीव्र था।

1.33 सकल स्थिर पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) संकेतकों ने वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में या तो संयमन (मॉडरेशन) या संकुचन (कॉन्ट्रैक्शन) दर्ज किया है। रिहायशी स्थानों अन्य भवनों एवं ढांचों में निवेश जो निर्माण सकल मूल्य योजन (जीवीए) द्वारा जाना जाता है, संभावित रूप से मंद रहा क्योंकि सीमेंट का उत्पादन एक वर्ष पूर्व के 16.3 प्रतिशत से घटकर अप्रैल-जून 2019 में 1.2 प्रतिशत हो गया था। इस्पात की खपत एक वर्ष पूर्व की 8.8 प्रतिशत के स्तर से नीचे गिरकर 2019-20 की पहली तिमाही में 6.6 प्रतिशत हो गई। अप्रैल-जून 2019 में पूंजीगत माल के उत्पादन में लगभग 2.4 प्रतिशत (एक वर्ष पूर्व 8.6 प्रतिशत) का गिरावट हुई तथा पूंजीगत वस्तुओं के आयात में 2019-20 की पहली तिमाही में गिरावट दर्ज की गई।

1.34 माँग को जागृत करने की दृष्टि से बुनियादी ढाँचे को आगे बढ़ाने के अनेक उपाय किए गए। इन उपायों में शामिल हैं राष्ट्रीय

महामार्ग कार्यक्रम की व्यापक पुनर्चना ताकि अपेक्षित लंबाई और क्षमता का राष्ट्रीय महामार्ग ग्रिड सृजित किया जा सके; रेलवे संबंधी बुनियादी ढाँचे जैसे ट्रैक का विकास और इसको पूरा करना, रोलिंग स्टॉक विनिर्माण तथा सवारी किराया सेवाएं देने के लिए सरकारी निजी सहभागिता (पीपीपी); और एयर क्राफ्ट वित्तपोषण, पट्टेदारी, तथा अनुरक्षण, मरम्मत एवं ओवरहॉल (एमआरओ) के लिए भारत को हब बनाना। परंपरागत उद्योगों के उन्नयन एवं पुनर्सृजन हेतु निधि योजना(एस एफ यू आर टी आई) से यह आशा की जाती है कि यह परंपरागत श्रमिक बहुल उद्योगों पर जोर देते हुए रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करेगी। अर्थव्यवस्था में कारोबारी सुगमता के लिए श्रमिक विनियमों को सरल व कारगर बनाने का कार्य भी किया जा रहा है।

1.35 मुद्रास्फीति परिदृश्य अनुकूल बना हुआ है और मॉनसून की भरपाई में हालिया प्रगति और खरीफ़ की बुवाई ने मॉनसून की देर से शुरुआत के कारण पूर्व की चिंताओं को कम कर दिया है। गर्मी के दिनों में सब्जियों और फलों के मूल्यों में सामान्यतया होने वाली वृद्धि से खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ी है। दालों और प्रोटीनयुक्त वस्तुओं की कीमतें भी 2019-20 के शुरुआती महीनों में बढ़ी हैं लेकिन यह देखना है कि ये दबाव कब तक बने रहते हैं। ईंधन और बिजली समूह में देखें, तो अंतरराष्ट्रीय कीमतों के अनुरूप एलपीजी की कीमतों के बढ़ने से 2019-20 की पहली तिमाही में कुछ ऊर्ध्वमुखी दबाव पड़ा है जो अब जुलाई तक आते-आते कुछ कम हो गया है। इसके विपरीत, खाद्यान्न और ईंधन को छोड़कर मुद्रास्फीति काफ़ी और व्यापक आधार में नरम पड़ी है, जो माँग के कमजोर होने को प्रदर्शित करती है, अलबत्ता जुलाई में इसमें कुछ सुधार हुआ। पहली तिमाही और जुलाई 2019 में हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति 3.1 प्रतिशत रही। अगस्त 2019 की तीसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के अनुसार अनुमान था कि जोखिमों के सम संतुलन के साथ 2019-20 की दूसरी तिमाही में मुद्रास्फीति 3.1 प्रतिशत व 2019-20 की दूसरी छमाही में 3.5-3.7 प्रतिशत के बीच रहेगी। वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही के लिए अनुमान था कि सीपीआई मुद्रास्फीति 3.6 प्रतिशत रहेगी।

1.36 इस पृष्ठभूमि में घरेलू वित्तीय बाज़ार अस्थिर रहे। इक्विटी बाज़ारों में 20 अगस्त, 2019 तक हानि दर्ज हुई है। हाल के महीनों में बीएसई सूचकांक ने 3 जून, 2019 के अपनी सर्वकालिक उँचाई के स्तर से नीचे ही ट्रेड किया है।

मई में व्यापार संबंधी तनाव घटने के बाद विश्व में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आने से भारतीय रुपए ने बढ़ने का रुख प्रदर्शित करना शुरू किया था। तथापि, अगस्त 2019 में चीन द्वारा दशक के निम्नतम स्तर तक अपनी मुद्रा का मूल्य-हास करने के कारण रुपया दबाव में आया। 2019-20 की पहली तिमाही में मुद्रा और सरकारी प्रतिभूति बाज़ार काफ़ी हद तक स्थिर बने रहे क्योंकि सरकारी नकदी राशियों के तेज़ी से निकासी (ड्राडाउन) और प्रचलन में मुद्रा (करेंसी) की माँग में गिरावट से दोनों हिस्सों में ब्याज दरों के कम बने रहने के कारण जून 2019 से ही चलनिधि के आधिक्य की स्थिति है। तथापि, आगे चलकर वैश्विक प्रभावों के प्रसार से अधोमुखी जोखिम आ सकते हैं।

1.37 भारत का बाह्य क्षेत्र परिदृश्य वैश्विक घटनाक्रमों, विशेषतः विश्व में मंदी के गहराने की संभावनाओं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के मूल्यों के बारे में अनिश्चितताओं तथा पूंजी प्रवाहों में अस्थिरता के अधोमुखी जोखिमों से प्रभावित हो सकता है। वर्ष 2019-20 के पहले चार महीने में भारत के निर्यात और आयात दोनों गिरावट की स्थिति में चले गए। 2019-20 की प्रथम तिमाही में 14.5 बिलियन अमरीकी डालर की निवल एफडीआई का मजबूत प्रवाह आया जबकि पिछले वर्ष यह 9.6 बिलियन अमरीकी डालर था। विदेशी पोर्टफोलियो में आने वाला निवल निवेश 2019-20 में अब तक (16 अगस्त 2019 तक) 2.4 बिलियन अमरीकी डालर रहा जबकि इसकी तुलना में वर्ष 2018-19 की इसी अवधि में बाहर जाने वाला निवल प्रवाह 8.2 बिलियन अमरीकी डालर था। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 16 अगस्त 2019 की स्थिति के अनुसार 430.5 बिलियन अमेरिकी डालर था जिसमें मार्च 2019 के अंत से 17.6 बिलियन अमेरिकी डालर की वृद्धि हुई है।

1.38 इस पृष्ठभूमि में, और विशेषतः निवेश गतिविधियों में धीमापन और हेडलाइन मुद्रास्फीति का पथ लक्ष्य से नीचे देखते हुए एमपीसी ने अप्रैल-अगस्त 2019 में नीतिगत दर को 85 आधार अंक घटा दिया (फरवरी 2019 में 25 आधार अंक घटाने के अतिरिक्त) और साथ ही जून 2019 में मौद्रिक नीति का रुख तटस्थ से बदलकर निभावी (एकोमोडेटिव) कर दिया। मौद्रिक नीति का संचालन इस उद्देश्य से निर्देशित होता रहेगा कि संवृद्धि को सहारा देते हुए, +/- 2 प्रतिशत की सहन-सीमा के अंदर 4 प्रतिशत सीपीआई मुद्रास्फीति के मध्यावधि लक्ष्य को प्राप्त किया जाए।

1.39 केंद्रीय बजट 2019-20 में यह अनुमान लगाया गया है कि 2019-20 के लिए सकल राजकोषीय घाटा 3.3 प्रतिशत रहेगा (2018-19 में 3.4 प्रतिशत)। अप्रैल-जून 2019-20 के दौरान सकल राजकोषीय घाटे का बजट अनुमानों के 61 प्रतिशत पर रहना एक वर्ष पहले की तुलना में कम था। प्राप्ति की बात करें तो, अप्रत्यक्ष करों के अंतर्गत सकल कर संग्रहण कम रहा जबकि प्रत्यक्ष करों की स्थिति अच्छी रही, वहीं कुल व्यय मामूली रूप से अधिक रहा। 2019-20 के दौरान राज्यों की राजकोषीय स्थिति के संबंध में, बजट अनुमानों में राजस्व तटस्थता और कम राजस्व घाटे की बात कही गई है, यद्यपि व्यय की गुणवत्ता में गिरावट का अनुमान लगाया गया है जिसमें राजस्व शीर्षों की तुलना में पूंजी व्यय में कम वृद्धि होगी। तदनुसार, 2019-20 में केंद्र और राज्य का सम्मिलित सकल राजस्व घाटा 5.7 प्रतिशत पर रहने का अनुमान लगाया गया है जो 2018-19<sup>2</sup> के 5.9 प्रतिशत के संशोधित अनुमानों से कम होगा। भविष्य में, उच्च पूंजी व्यय के गुणकों को देखते हुए, बिना सार्वजनिक ऋण संग्रहीत किए संवृद्धि को बढ़ाने के लिए राजकोषीय पुनर्समायोजन हेतु इन्फ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक क्षेत्र के व्यय में सुधार की दरकार है। राजस्व की ओर, अनुपालन की सुगमता में सुधार के लिए नए प्रयासों के साथ, जीएसटी और डिजिटलाइजेशन की पूरी क्षमता के दोहन से कर की दरों में, जहां संभव होगा, कमी करने की गुंजाइश बढ़ेगी, साथ ही राजस्व तटस्थता भी बनी रहेगी।

1.40 2019-20 के दौरान, बैंकिंग क्षेत्र पिछले वर्ष में प्राप्त समेकन के आधार पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। रिजर्व बैंक<sup>3</sup> द्वारा ऋण जोखिम के लिए किए गए दबाव परीक्षणों से पता चलता है कि बेसलाइन परिदृश्य के अंतर्गत, मार्च 2020 तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल अनर्जक आस्ति अनुपात और गिरकर 9.0 प्रतिशत तक पहुँच सकता है (मार्च 2019 में 9.1 प्रतिशत)। इससे प्रावधानीकरण को गुंजाइश मिलेगी, वित्तीय प्रदर्शन में सुधार होगा और अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों के लिए ऋण प्रवाह को और गति तथा व्यापकता मिलेगी। इसके साथ ही, बैंकिंग प्रणाली की सुदृढ़ता को बल

देने के लिए कई विनियामी और पर्यवेक्षी कदम उठाए जा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (ए) बैंकों में कंपनी अभिशासन (कॉरपोरेट गवर्नेंस); और (बी) परिचालनात्मक जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी अपेक्षाओं की गणना हेतु संशोधित मानकीकृत पद्धति पर दिशा निर्देशों का प्रारूप जारी करेगा जिससे वर्तमान विनियामी फ्रेमवर्क को विश्व की सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बनाया जा सके। इसके अलावा, ऋण जोखिम और प्रतिभूतिकरण के लिए पूंजी प्रभार पर संशोधित दिशा-निर्देश का प्रारूप (ड्राफ्ट) जारी किया जाएगा। बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम के लिए विनियामी फ्रेमवर्क को अंतिम रूप दिया जाएगा। ये उपाय जून 2019 में समस्याग्रस्त आस्तियों के लिए बनाए गए संशोधित विवेकपूर्ण फ्रेमवर्क और 1 अप्रैल 2019 से लागू व्यापक एक्सपोजर फ्रेमवर्क के साथ काम करेंगे जिससे एक विवेकपूर्ण ऋण संस्कृति को प्रोत्साहित किया जा सके।

1.41 बैंकों के लिए नॉन-ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी के स्वरूप में अंतरण के प्रयोजन से एक चर्चा पत्र और इसके पश्चात अंतिम दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। उभरते फिनटेक परिदृश्य में, एक विनियामी सैण्डबॉक्स फ्रेमवर्क चालू किया जाएगा। विधायी संशोधनों के अधीन, बैंकों और एआईएफआईए के भारतीय लेखांकन मानदंडों को रिजर्व बैंक अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाएगा जिससे उन्हें अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) के समरूप लाया जा सके। प्रणाली में शुरुआती ऋण जोखिमों पर विचार हेतु, बैंकों के लिए समष्टि-विवेकपूर्ण नीतियों के कार्यान्वयन पर एक चर्चा पत्र जारी किया जाएगा। बाजार तंत्र के माध्यम से बड़े उधारकर्ताओं को ऋण आपूर्ति के लिए बने फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के पुनर्मूल्यांकन के लिए, बैंकों/ बड़े क्रेडिट पर सूचना का केंद्रीय भंडार (सीआरआईएलसी) के डेटा की जांच की जाएगी। बैंक ग्राहकों के लिए डिजिटल ऑनबोर्डिंग सुगम किया जाएगा जिसमें वर्तमान धन शोधन निरोधक (पीएमएल) नियमावली नियमों के फ्रेमवर्क के अंतर्गत व्यक्तियों के लिए वीडियो आधारित केवाईसी सक्रिय किया जाएगा।

<sup>2</sup> ऑकड़े 27 राज्यों से संबंधित हैं।

<sup>3</sup> वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, जून 2019।

1.42 प्रतिभूतिकरण और कंपनी बॉन्ड बाजार का विकास करने और इसमें गहनता लाने के लिए रिज़र्व बैंक ने आवास वित्त प्रतिभूतिकरण बाजार के विकास पर एक समिति (अध्यक्ष: डॉ. हर्षवर्धन) और कंपनी ऋणों के लिए द्वितीयक बाजार के विकास पर एक कार्यदल (अध्यक्ष: श्री टी एन मनोहरन) बनाया है। सहकारी क्षेत्र के बैंकों की आर्थिक स्थिति पर पर्याप्त जानकारी प्राप्त करने के हेतु पर्यवेक्षी प्रक्रिया को तदनुसार ठीक करने हेतु आगामी निरीक्षण चक्र से एक बेहतर रेटिंग फ्रेमवर्क शुरू किया जा रहा है। प्रस्ताव है कि यूसीबी क्षेत्र में धोखाधड़ी की घटनाओं को केंद्रीकृत धोखाधड़ी (सेंट्रलाइज्ड फ्रॉड) रजिस्ट्री में रिपोर्ट किया जाए जिसे सभी यूसीबी देख सकें।

1.43 रिज़र्व बैंक एनबीएफसी की आस्ति-देयता प्रबंधन (एएलएम) के फ्रेमवर्क को मजबूत करना चाहता है। संघीय बजट 2019-20 में की गई घोषणा के अनुसार भारत सरकार ने एक योजना शुरू की है जिसके अनुसार वित्तीय रूप से मजबूत एनबीएफसी/आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) से कुल ₹1 ट्रिलियन तक उच्च रेटिंग की पूलड आस्तियों की खरीद करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को उनकी प्रथम हानि के 10 प्रतिशत तक की एकबारगी आंशिक ऋण (क्रेडिट) गारंटी देने का प्रस्ताव है। इस नीतिगत उपाय से एनबीएफसी को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से फंडिंग प्राप्त करने में मदद मिलेगी। अपनी तरफ से रिज़र्व बैंक, बैंकों को उनकी अतिरिक्त जी-सेक होल्डिंग पर अपेक्षित चलनिधि बैंकस्टॉप प्रदान करेगा। एनबीएफसी और एचएफसी को दिए गए वृद्धिशील ऋण (इन्क्रिमेंटल क्रेडिट) के लिए 01 अगस्त और 01 दिसंबर 2019 दोनों के लिए निर्धारित बैंकों के एनडीटीएल के 0.5 प्रतिशत के चलनिधि व्याप्ति अनुपात हेतु चलनिधि प्राप्त करने की सुविधा (एफएलएलसीआर) में की गई वृद्धि को रिज़र्व बैंक शुरुआत में पहले ही दे चुका है और यह 05 जुलाई 2019 की स्थिति के अनुसार एफसी और एचएफसी को जुलाई 2019 में दिए गए बकाया शेष के अतिरिक्त है। डिबेंचर शोधन रिज़र्व (डीआरआर) को समाप्त करने से एनबीएफसी को बॉण्ड जारी करने में सहूलियत होगी।

1.44 भुगतान प्रणाली विज्ञान 2019-21 में की गई परिकल्पना के अनुसार भुगतान और निपटान के क्षेत्र में भारतीय रिज़र्व बैंक प्रत्येक भारतीय को संरक्षित, सुरक्षित, सुविधाजनक, तेज और किफ़ायती ई-पेमेंट के विविध विकल्प प्रदान करना चाहता है। आरटीजीएस और एनईएफटी प्रणालियों में प्रोसेस किए गए लेन-देनों के लिए, रिज़र्व बैंक ने अपनी ओर से लगाए गए प्रभारों को समाप्त कर दिया है। समस्त एटीएम प्रभारों व फ़ीस के मामले में भी रिज़र्व बैंक कार्रवाई की समीक्षा कर रहा है। डिजिटल भुगतानों की गहनता पर बनी उच्च स्तरीय समिति (अध्यक्ष : श्री नंदन निलेकनी) की सिफ़ारिशों का लक्ष्य है कि डिजिटल भुगतानों (पेमेंट्स) की संरक्षा व सुरक्षा को मजबूत किया जाए और डिजिटल पेमेंट्स के विस्तार के लिए मध्यावधि रणनीति बनाई जाए। सभी उधारकर्ताओं के बारे में समग्र 360-डिग्री जानकारी लगभग वास्तविक समय पर देकर ऋण सूचना अवसंरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) को मजबूत बनाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं जिससे ऋण संस्थाओं को शीघ्र व कुशल ऋण निर्णय लेने में सुविधा हो।

1.45 वर्ष के दौरान केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीआइएमएस) के कार्यान्वयन से, मशीन लर्निंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के साथ बड़ी मात्रा में स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की प्रोसेसिंग के लिए अत्याधुनिक बिग-डेटा आधारित सूचना प्रबंधन तंत्र उपलब्ध होगा। सीआईएमएस एक डेटा साइंस लैब प्लेटफॉर्म, एक ग्रेन्यूलर डेटा एक्सेस लैब (जीडीएल), एक केंद्रीकृत विश्लेषणात्मक लेयर और विनियमित संस्थाओं से डेटा का स्वचालित प्रवाह उपलब्ध कराएगा।

1.46 वर्ष 2019-20 में उपभोक्ता माँग और निजी निवेश को पुनः जाग्रत करना सर्वोच्च प्राथमिकता पर है। इसमें बैंकिंग क्षेत्र और गैर-बैंकिंग क्षेत्रों को सुदृढ़ बनाना, आधारभूत संरचना में व्यय के बड़े प्रयासों तथा श्रम कानूनों, कराधान और अन्य अति आवश्यक संरचनात्मक सुधारों को लागू करना शामिल होगा, जिससे कारोबारी सुगमता भी बढ़ेगी और 2024-25 तक भारत के 5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के विज्ञान को पूरा करने की दिशा में कार्य किया जा सकेगा।